and 30th, January, 1992, at New Delhi between the trade delegations of the two countries. On its conclusion, a Joint Statement was issued. In the meeting, the Japanese side assured that they could consider buying raw materials and components for the use of Japanese companies in India if these met their standard and the prices were competitive.

(b) and (c) No such agreement was reached and no specific joint ventures agreed upon for component exports.

भारतीय काजू निगम का कारोबार

4494. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय काजू निगम का इस समय कुल कितना कारोबार है तथा इसकी बिक्री और खरीद के आंकड़े क्या हैं और इनका पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके कितने खरीद-केन्द्र हैं और प्रत्येक केन्द्र पर कितना-कितना काजू खरीदा जाता है और कितने-कितने काजू को संसाधित किया जाता है तथा कितना संसाधित काजू बाजार से खरीदा जाता है और विदेशों को बेचे जाने वाले काजू का देश-वार विक्रय मूल्य कितना-कितना है तथा देश में इसका विक्रय मूल्य कितना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) और (ख) कैश्यू कारपोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना विभिन्न पात्र वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए कच्चे काजू आयात हेतु एक सरणीयन अभिकरण के रूप में की गई थी। कच्चे काजू के आयात का सरणीयन वर्ष 1991 में समाप्त किया गया और पात्र वास्तविक प्रयोक्ताओं को ओ.जी.एल. के तहत कच्चा काजू आयात करने की अनुमति दी गई। तब से कच्चे काजू के आयात के बारे में कैश्यू कारपोरेशन आफ इण्डिया की भूमिका आयात संविदाओं के पंजीकरण तक ही सीमित रखी गई जिसके लिये वह सी आई एफ मूल्य के 0.25% की दर से पंजीयन शुल्क एकत्र करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कैश्यू कारपोरेशन आफ इण्डिया के निर्यात कारोबार के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं:

लाख रु०

1989-90	1990-91	1991-92
785.27	962.09	2344.09 (29.2.92 तक)

यह निगम कच्चे काजू की खरीद तथा बिक्री नहीं करता है और उसके नियंत्रणाधीन न तो कोई खरीद केन्द्र है और न ही कोई प्रसंस्करण एकक है।

Export of Dyes

4495. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's exports of dyes have touched Rs. 850 crores in 1991-92 as reported in the news-item published in the 'Economic Times' of the 19th February, 1992;

(b) whether exports of H-acid, a dye-intermediate, which caused serious pollution at Bichhri in Rajasthan was of the order of Rs. 50 crores;

(c) what are the details of H-acid manufactures in the country; State-wise;

(d) whether it is also a fact that manufacture of H-acid has been banned or is being discouraged in many developed countries; and

(e) if so, what in India's reaction thereto particularly in view of Bichhri and other unreported experience?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Basic Chemicals Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL) Bombay has reported that export of dyes and intermediates for the period April 1991—February 1992 has been to the tune of Rs. 655.1 crores and that during the year 1991-92 the exports are likely to achieve the level of Rs. 882 crores.

(b) It is known that dyestuff industry in general creates pollution problems. Exports from Bichhri are not known, as state-wise export figures are not maintained.

(c) Statewise figures are not readily available.

(d) and (e) As per the information available, no developed country has put a ban on the manufacture of H-acid. However, due to rising costs and low returns, many units in the developed countries are gradually phasing out the manufacture of dye stuffs and

increasingly sourcing their requirements from India, China and South Korea etc.

भारतीय चाय व्यापार निगम में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

4496. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में भारतीय चाय व्यापार निगम ने कितने व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति की है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनुपात का पालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो, उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में बकाया रिक्तियों को कब तक भरा जायेगा; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 27 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और 111 व्यक्ति पदोन्नत किए गए।

(ख) जी हां।

(ग)

	कुल	अ.जा.	अ.ज.ज	बकाया रिक्तियां	
				अ.जा	अ.ज.जा.
नियुक्ति	27	4	1	शून्य	1
पदोन्नति	111	18	1	शून्य	7

(घ) और (ङ) अ०ज०जा० संवर्ग की बकाया रिक्तियों को मुख्य रूप से इस वर्ग में उपयुक्त / पुरुष उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सका है। इस संबंध में सरकार की नीति के अनुसार बकाया रिक्तियों को भरने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

Demand for Allotment of Accommodation to Tea Board Staff

4497. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the serious problems of residential accommodation faced by the Tea Board staff working in the Parliament House; and

(b) whether Government propose to allot accommodation to above Tea Board Staff from Government's pool as is being done for the other Private sector units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No such problem has been brought to the notice of the Government by the Board. Tea Board staff are not provided with residential accommodation from the government pool. However, Tea Board has reserved some flats under construction in the Ghaziabad Housing Development Authority for their staff in Delhi, including those who are working in the Parliament House.

Dues Under C.C.S. and Supplementary C.C.S. in lieu of Duty Drawbacks

4498. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 361 and Unstarred Questions 2634, 2636 and 2644 given in the Rajya Sabha on the 17th December, 1991 and state:

(a) what are the total dues under C.C.S. and supplementary C.C.S. in lieu of Duty Drawback that is still outstanding to be paid to exporters or deemed exporters;

(b) whether it is a fact that he had stated that outstanding arrears in CCS payments will be made within 3 to 4 weeks;

(c) if so, what are the reasons that the outstandings/refunds have not yet been paid;

(d) whether Government have received any representation from any of the deemed exporters;

(e) if so, what are the exact details thereof; and